तिक विपदा को देखते हुए किसानों की लगान, आवपाशी व सभी सरकारी वसूलयावी व बैंकों को जमा करने वाली किश्तें अगली फसल तक स्थगित कर दें। तथा इस समय उनको खाद, बीज तथा अन्य जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा जिन लोगों की जन-धन तथा अन्य प्रकार की हानि हुई है उन्हें भी आर्थिक सहायता पहुंचा कर राहत दिलायें तथा रोगों से पीड़ित लोगों को दवाओं आदि की व्यवस्था सुलभ कराई जाये।

(iii) Need for Television Facilities at Mangalore and Udipi

SHRI OSCAR FERNANDES (Udipi) : **In Karnataka State Udipi in South Kanara district is the popular pilgrim centre because there is the famous temple of Krishna and it is a centre of study for Dvaita philosophy. Mangalore is the port town of historical importance. They are attracting visitors from various parts of the country. They are progressing very fast in the entire State. In spite of this, the people are deprived of television facilities. There is a long standing demand from the people of this area for a television centre and the centre has to look into this request sympathetically. Mangalore and Udipi have become forerunners in industrial and agricultural fields in the State and in the field of education these areas are far ahead of all centres of the State. If television facilities are provided to this area then it would provide further impetus for other areas of the State to emulate the efforts of Mangalore and Udipi.

South Canara is predominantly dominated by backward classes and many of them are depending upon agriculture. The 'Krishi-darshan' over television will inspire the agriculturists here. Mangalore and Udipi centres already have microwave stations and, therefore, television facilities can be provided here by spending just two or three lakhs.

Therefore, I urge the hon. Minister for Information and Broadcasting to sanction television facilities to Mangalore and Udipi immediately. I also request him to speed up the work of setting a fullfledged television centre for the State.

(iv) Effective Implementation of the 20-Point Programme in Bihar

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) उपाध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक विकास हेतु प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का सूत्रपात किया है और इसके पूर्ण क्रियान्वयन हेतु केन्द्र ने राज्य सरकारों को राय दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नई-नई योजनायें चालू करें ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके। समाज के कमजोर वर्ग हरिजन व आदिवासियों की स्थिति सुधारने हेतु आर्थिक बिकास में तीव्रता लानी होगी। बिहार में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पीने का पानी उपलब्ध कराने, बृक्षारोपण, बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लागू करने, भूमिहीनों को जमीन का आवंटन, मकान हेतु जमीन दिलाने की तत्काल व्यवस्था करनी है और जनता को सुख-चैन हेतु आश्वस्त भी तभी किया जा सकता है जब समाज का बहुमुखी विकास हो, अन्यथा सारा प्रयास अधूरा रह जायेगा। गावों में विद्युतीकरण किया जाये। वायोगैस संयंत्र लगाये जायें तथा लिंक मार्ग मनाये जायें। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उपयुक्त निर्देश दे कि सामाजिक सुरक्षा की नई योजनायें तुरन्त तैयार की जायं और उन्हें तत्काल लागू किया जाये। कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली पम्पसेट खरीदने के लिए 33 प्रतिशत आर्थिक सहायता के स्थान पर और अधिक सहायता दी जाये। छोटे किसानों को बिजली के कनेक्शन हेतु अधिक वित्तीय सहायता दी जाये।

बिहार का भविष्य तेजी से आर्थिक विकास की योजनाओं व 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू

**The original speech was delivered in Kannada.

करने में है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा सुझाव है कि वह 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने हेतु बिहार सरकार को अधिक सहायता राशि प्रकान करे ताकि बिहार का आर्थिक उत्थान हो सके और वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में आ सके।

(v) Need for opening an Industrial Training Institute at Samastipur (Bihar)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार यों ही बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें भी समस्तीपुर जिला तो औद्योगिक एवं कृषि जनित प्रचुर संभावनाओं के बावजूद भी अत्यन्त ही पिछड़ा है। यहां की उपजाऊ भूमि, लोगों की कर्मठता, उनमें आर्थिक विकास के प्रति उत्साह एवं केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विशेष कार्यक्रमों के बावजूद भी यहाँ के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। ग्रामीण विकास के केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम भी ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। इससे लगता है कि सत्प्रयासों में निश्चय ही कहीं न कहीं कोई त्रुटि अवश्य है और यह है प्राथमिकता के चयन में गलती। विभिन्न कार्यक्रमों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित नवयुवकों में तकनीकी शिक्षा का अभाव है और इस परिस्थिति में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय चाह कर भी उन नवयुवकों की सहायता करने में असमर्थ हैं। मूल कारण है जिले में किसी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का न होना। इस अभाव के कारण उत्सुक नवयुवकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने में कठिनाई हो रही है। इस कमी को दूर करने के लिए समस्तीपुर में एक पोलिटिकल अथवा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (आ०टी०आई०) खोलने की आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से इस अंचल में एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान खोलने की पुरजोर मांग करता हूं।

(vi) Need for effectively curbing the activities of Dr. Jagjit Singh and his supporters

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत 18 अप्रैल को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के समक्ष डा० जगजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में खालिस्तान समर्थकों तथा अकालियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 11 संगठनों के 150 प्रदर्शनकारियों ने उक्त प्रदर्शन में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि उत्तरी अमेरिका अकाली दल, जो श्री हरचन्दसिंह लोंगोवाल से सम्बद्ध है, भी प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ। डा० चौहान तथा उत्तर अमेरिका अकाली दल के अध्यक्ष सुखमन्दर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एक ज्ञापन भी दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिन 11 संगठनों की ओर से ज्ञापन दिया गया, उनमें श्री लोंगोवाल का शिरोमणि अकाली दल भी सम्मिलित था। ज्ञापन प्रस्तुत करने के पश्चात् डा० चौहान ने यह भी बताया कि उनका विचार जेनेवा स्थित मानव अधिकार केन्द्र को भी अगले माह एक ज्ञापन देने का है। प्रदर्शनकारी "स्टाप जेसेकर आफ सिख्स तथा "सिख्स आर ए नेशन" के नारे लिए हुए थे।

इस प्रकार विदेशों में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड आदि में खालिस्तान के समर्थकों की चेष्टाएं बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार ने डा० चौहान का पासपोर्ट निरस्त कर दिया है। वह इंग्लैन्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र पर अन्य देशों की यात्राएं कर रहा है। उसका कृषि विषयों से कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसा कहा जाता है कि फिर भी कृषि विषयक विचार-विमर्श हेतु, अमेरिकन सीनेट